395

संख्याः–545/XIV–1/2014–5(8)/2010

प्रेषक,

प्रदीप सिंह रावत,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निबन्धक,
सहकारी समितियां, उत्तराखण्ड।

सहकारिता, गन्ना एवं चीनी अनुभाग–1 देहरादून, दिनांक 23 मई , 2014

विषयः–सहकारिता विभाग के अन्तर्गत राज्य सहकारी परिषद के संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2014–15 में प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके कार्यालय पत्र संख्या–269/नियो0/सह0परिषद/2014–15 दिनांक 11 अप्रैल 2014, वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत करने विषयक वित्त विभाग के पत्र संख्याः–318/XXVII (1)/2014 दिनांक 18 मार्च, 2014 व अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या–80/अ0मु0स0/पी0एस0/ 2014–15 दि0 23 अप्रैल, 2014 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सहकारिता विभाग के अन्तर्गत राज्य सहकारी परिषद के संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2014–15 के आय–व्ययक में प्राविधानित धनराशि में से **₹9,00,000/-(रूपये नौ लाख मात्र)** की धनराशि निम्नांकित शर्तों के अधीन व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

1. बजट प्राविधान से अधिक किसी भी दशा में न तो व्यय किया जाय और न ही पुनर्विनियोग व अन्य माध्यम से अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में कोई व्ययभार/दायित्व सृजित किया जाय।
2. व्यय करने के पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो, उनमें व्यय करने के पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।
3. बजट मैनुअल में निर्धारित प्रक्रिया के अधीन कोषागार द्वारा प्रमाणित वाउचर संख्या एवं दिनांक के आधार पर अंकित बजट की सीमा में आहरण एवं वितरण अधिकारी प्रतिमाह की 5 तारीख तक बी0एम0–5 प्रपत्र पर ठीक पूर्व माह की सूचना विभागाध्यक्ष को तथा बी0एम0 13 प्रपत्र पर 20 तारीख तक विभागाध्यक्ष द्वारा उक्त सूचना वित्त विभाग एवं प्रशासकीय विभाग को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जाय तथा बजट मैनुअल के विभिन्न प्रपत्रों के माध्यम से शासन तथा महालेखाकार कार्यालय को समय से सूचना भेजा जाना सुनिश्चित किया जाय।
4. स्वीकृत धनराशि निर्धारित मद में ही व्यय की जायेगी एवं व्यय करते समय वित्त विभाग के मितव्ययता सम्बन्धी समय–समय पर जारी शासनादेशों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
5. उक्त स्वीकृति के व्यय के अनुश्रवण की नियमित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। यदि किसी मामले में सीमाधिक व्यय दृष्टिगोचर हो तो निबन्धक द्वारा उसे तत्काल वित्त विभाग एवं शासन के संज्ञान में लाया जाए।
6. वचनबद्ध तथा अवचनबद्ध मदों के सम्बन्ध में वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 18 मार्च, 2014 में उल्लिखित समस्त शर्तों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
7. आहरण वितरण अधिकारी अपने स्तर से निम्नानुसार फॉट कर बजट उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा सम्भावित व्यय की फेजिंग कर उसकी सूचना शासन तथा वित्त विभाग को उपलब्ध करायी जाय–

क्रमशः

(धनराशि हजार रूपये में)

व्यय की मदें	स्वीकृत धनराशि
यात्रा व्यय	25
अन्य भत्ते	45
मानदेय	60
कार्यालय व्यय	25
विद्युत देय	10
जलकर/जल प्रभार	3
लेखन सामाग्री और फार्मों की छपाई	15
कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	15
टेलीफोन पर व्यय	25
गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	213
व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	285
किराया उपशुल्क और कर स्वामित्व	120
आतिथ्य व्यय विषयक भत्ता आदि	12
अन्य व्यय	12
कम्प्यूटर हार्डवेयर	25
कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का कय	10
योग	900

(रूपये नौ लाख मात्र)

2– उक्त स्वीकृति के अधीन व्यय चालू वित्त वित्तीय वर्ष 2014–15 के अनुदान संख्या–18 के लेखाशीर्षक 2425–सहकारिता–आयोजनागत–00–800–अन्य व्यय–20–सहकारी परिषद का गठन एवं संचालन–00–मानक मद 20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के नामे डाला जायेगा।

3– ये आदेश वित्त विभाग की अशा0 संख्या–02(p)/XXVII–4/2014, दिनांक 15 मई, 2014 द्वारा प्रदत्त स्वीकृति के कम में जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक–आई0डी0 मूल में।

भवदीय,

(प्रदीप सिंह रावत)
अपर सचिव।

क्रमशः

संख्याः–545(1)/XIV–1/2014, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, ओबरॉय बिल्डिंग, माजरा, देहरादून, उत्तराखण्ड।
2. वित्त–4/नियोजन/भाषा अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, अल्मोड़ा, उत्तराखण्ड।
4. सचिव, उत्तराखण्ड राज्य सहकारी परिषद, देहरादून (द्वारा निबन्धक)।
5. बजट निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।
6. प्रभारी, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
7. प्रभारी मीडिया सेन्टर, सचिवालय परिसर, देहरादून।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र कुमार भट्ट)
अनु सचिव।